

(c) Several rounds of talks have been held at various levels on the foreigners issue in Assam but no agreed understanding has emerged.

Government has kept its doors open for talks and it is hoped that saner counsels will eventually prevail amongst the agitators.

Purchase by NCC Part Time Commissioned Officers from Military Canteens

2308. SHRI JAMBUWANT DHOTE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a part time Commissioned Officer working in Senior Secondary Schools, is authorised to purchase all types of stores from Military Canteens;

(b) if so, whether he is also authorised to buy liquor, imported items and specially allocated items;

(c) whether he is issued any card for these types of purchases; and

(d) if not, whether Government are thinking to do so, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) No. Sir. Part-time Commissioned Officers of National Cadet Corps are authorised to purchase only general stores of Indian origin ex-CSD Canteen.

(b) No, Sir. Liquor is not authorised to such officers. Nor are they authorised to purchase imported and specially allotted items.

(c) The question does not arise in the light of answer given above in part (b) of the question.

(d) No, Sir. In view of their specific duties and responsibilities, the part time Commissioned Officers of the National Cadet Corps who are pri-

marily civilian officers, cannot be treated on par with commissioned officers of the Defence Services.

हथियारों की तस्करी

2309. श्री केशव राव पारधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हथियारों की तस्करी में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली गतिविधियों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) जनवरी, 1980 से ले कर अक्टूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान पकड़े गये तस्करी के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके द्वारा कितनी तस्करी की गई है; और

(ग) भविष्य में अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ग) सरकार को देश में हथियारों की तस्करी की जानकारी है। राज्यों से अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान चलाने और इस सम्बन्ध में संतर्क रहने के लिए कहा गया है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी सीमा क्षेत्रों में विशेष गस्त और छापे आयोजित किए गए हैं।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना से पता चलता है कि तस्करी के 260 हथियार जप्त किए गए हैं। अभी तस्करी के नामों और अन्य विवरणों को बताना अनिष्ट है

नहीं होगा क्योंकि इस से भविष्य में सस्तर तस्करों के विरुद्ध किये जाने वाले कार्य में बाधा पड़ सकती है।

बड़े बांधों के लिये सीमेंट की मांग

2310. श्री विहास मुत्तेस्वार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और बिजली के लिए बड़े बांधों की मांग को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) कितने नये सीमेंट कारखानों की स्थापना की जाएगी और वह कहाँ कहाँ पर की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजित बानना) : (क) योजना आयोग द्वारा सीमेंट उद्योग पर स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार 1984-85 तक 372.6 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने लगेगा।

(ख) सीमेंट के नये कारखानों की स्थापना करने के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	अदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश
2.	-उपरोक्त-	तेंदूर	-उपरोक्त-
3.	-उपरोक्त-	येरागन्तला	-उपरोक्त-
4.	-उपरोक्त-	नीमल	मध्य प्रदेश
5.	-उपरोक्त-	अकलतरा	-उपरोक्त-
6.	-उपरोक्त-	दिल्ली	दिल्ली
		भटिंडा	पंजाब
7.	जे० एण्ड के० मिनिरलस लि०	बशोली	जम्मू एण्ड काश्मीर
8.	-उपरोक्त-	खिंड	-उपरोक्त-
9.	यू०पी० स्टेट कारपोरेशन	डैल्ला/चुनार	उत्तर प्रदेश
10.	मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	गारो पहाड़ियाँ	मेघालय
11.	-उपरोक्त-	लमशांग	-उपरोक्त-
12.	केरला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	गेंगलाघाट	केरला
13.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०, कलकत्ता	मधुकुड	पश्चिम बंगाल
14.	राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	काटपुतली	राजस्थान